

## न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी— इन्द्र सिंह राव आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 341/2016

बउनवान

रामप्रसाद आयु 50 साल पुत्र श्री मन्नालाल जाति—गुसाई निवासी—बालुन्दा  
तहसील—मॉंगरोल, जिला—बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, मॉंगरोल (रेस्पोंडेंट)

**अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956**

उपस्थिति :-1. श्री मो० रफीक कुरैशी, अभिभाषक

(अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 25.11.2020

1— अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉंगरोल के आदेश दिनांक 18.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—बालुन्दा, तहसील—मॉंगरोल की आराजी खसरा नम्बर 147, 361 रकबा 0.92 है० किस्म गै.मु.नाला पर अतिक्रमी मानकर फसल जप्ती, बेदखली, 400/- रुपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी व जवाबदेही का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतिक्रमित आराजी की पैमाईश नहीं की गयी है। अतिक्रमित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। ना ही सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर एकपक्षीय आदेश पारित करने की भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉंगरोल का आदेश दिनांक 18.2.2016 निरस्त फरमाया जावे।

2— इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।



3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, कब्जा पूर्व से छोड़ रखा है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जाँच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट व बयानों को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 69/15 निर्णय दिनांक 23.2.2015 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी गै.मु.नाला है जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 69/15 निर्णय दिनांक 23.2.2015 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉंगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 62/2016 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)  
जिला कलक्टर, बारां